



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री

## राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

### विकास एवं सुशासन उत्सव

लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण

मुख्य अतिथि

## श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

28 मार्च, 2025 | चित्रकूट धाम स्टेडियम, भीलवाड़ा | अपराह्न 12:00 बजे

#### शुभारंभ / विमोचन

- राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारम्भ
- सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन
- ई-उपचार एप का लांच

#### योजनाओं के दिशा निर्देश/आदेश

- स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण
- फायर एन.ओ.सी. प्रक्रिया का सरलीकरण
- रजिस्ट्री अब सप्ताह में 2 दिन प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक
- हरित अरावली विकास परियोजना
- नये जिलों में डी.एम.एफ.टी. गठन
- राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भण्डार

विकसित राजस्थान - समृद्ध राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

## विचार बिन्दु

दूसरों पर शक करना कभी-कभी गुनाह हो जाता है। -कुरान

## क्या सिद्धारमैया सरकार का ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का कोई औचित्य है?

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिनांक 14.03.2025 को केबीनेट की मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्वोरमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर किया गया। इसे विधानसभा में पेश किया जावेगा। इससे पूर्व सरकार ने बजट सत्र के समय घोषणा की थी कि सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जावेगा और यह आरक्षण श्रेणी II की अन्तर्गत आयेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर लागू होगी। एस्सी, एससी और ओबीसी को इसमें पहले से आरक्षण है। जो श्रेणी I, श्रेणी II ए में है। अब इसमें श्रेणी II को जोड़ा जायेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय है। आरक्षित वर्ग के ऐसे ठेकेदार 2 करोड़ तक के ठेके के अधिकारी (पात्र) होंगे। इस प्रकार कर्नाटक में सरकारी टेन्डर व ठेकों में मुस्लिमों को 4% कोटा देने की तैयारी करली है। यह कहा गया है कि 4% आरक्षण ओबीसी केटेगरी में होगा, जिसे 4% मुस्लिम ओबीसी केटेगरी के मापदण्डों की पूर्ति नहीं करेते।

भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय राज्य के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुये कहा कि कांग्रेस नेता ने कथित संवैधानिक सिद्धान्तों पर साम्प्रदायिक लुट्टिकरण को प्रार्थमिकता देने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 मार्च 2025 को सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का असंवैधानिक कदम कहा है और इसे न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। दिनांक 24.03.2024 को संसद में भी भाजपा ने आरक्षण का विरोध करते हुये, उसे असंवैधानिक बतलाया।

आरक्षण के प्रावधान संवैधानिक के भाग 16 में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ वर्गों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 330, 331, 332, में आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख हमें भाग 16 में मिलेगा। अनुच्छेद 334 में लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के लिये एस्सी व एससी के आरक्षण के प्रावधान हैं। पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान भी आप इसी भाग में पढ़ सकते हैं। संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 342ए जोड़ा गया है। यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिये है।

केरल, बिहार, तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व उत्तरप्रदेश में मुस्लिमों के लिये आरक्षण का विशेष प्रावधान है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण है। जबकि अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय भी हैं। आर्थिक आधार पर तथा प्रोमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। अब तो यह कहा जा रहा है कि रेल के टिकटों पर भी आरक्षण की मांग होगी।

संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में मिलता है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। साधारण रूप से हम कह सकते हैं बहुसंख्यक के विपरीत जो संख्या में कम है व अल्पसंख्यक है। देश के कुछ लोगों की यदि कोई विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है तो उसके अनुसार उन्हें आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार भी है। सरकार उनके कार्यों में कोई दखल भी नहीं देती। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना अदृश्य है। अनुच्छेद 14 में Right to Equality यानी समता का अधिकार दिया और अनुच्छेद 15 में घोषणा की कि धर्म, मूलवर्ण जाति, लिंग का जन स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही यह भी निर्दिष्ट दे दिया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागिकों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये व्यवस्था करने से अन्य कोई बात होने पर उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगा।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 लाया गया था। इस अधिनियम की धारा 2(सी) में अल्पसंख्यक की परिभाषा है, इसके अनुसार अल्पसंख्यक वह है जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर करेगी। अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) इस प्रकार है:— (c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किया और प्रारम्भ में केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई,

वस्तुतः 4% मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी के केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) में है, वह तो प्रत्यक्षतः ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वयं ही अर्थ शून्य हो जायेगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में किसी कॉम्प्यूटिड को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को था। अब राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। अधिनियम 1992 की धारा 2(सी) में अल्पसंख्यक की परिभाषा में यह कहा गया है कि जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर करे वह अल्पसंख्यक है। केन्द्र सरकार ने निरंकुश होकर, बिना किसी वार्तिक के उक्त परिभाषा दी है। कानून की दृष्टि से यह अनुच्छेद 14 के अनुसार अवैध है, चूंकि अमर्यादित है निरंकुश है। फिर 4% आरक्षण ओबीसी केटेगरी में देने का कोई औचित्य ही नहीं है।

साधारण भाषा में अल्पसंख्यक का अर्थ है मेजोरीटी के विपरीत, बड़े गुप से छोटा गुप। माइनोरिटी के तीन रूप हैं, राजनीतिक, धार्मिक व भाषाई माइनोरिटी। इनमें से धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक के बाबत उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 में मिलता है, किन्तु राजनीतिक अल्पसंख्यक को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस का निर्णय बड़ी पीठ का निर्णय है। इस केस में यह स्पष्ट निर्णय है, चूंकि कि देश का पूर्णतः भाषा के आधार पर है अतः अल्पसंख्यकों का निर्णय भी उसी प्रकार होना चाहिये। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस में यह स्पष्ट किया है कि चूंकि पूर्व से राज्यों में ईसाई मेजोरीटी है अतः हिन्दू वहां अल्पसंख्यक है। जन्म कर्मिण में मुस्लिम बहुमत में है अतः हिन्दू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से अधिप्राय है धार्मिक अल्पसंख्यक है। जैनों को अल्पसंख्यक इसलिए माना कि जैन धर्म वैदिक धर्म से पूर्व का है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है, अतः यह कहना गलत है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म का भाग है। उक्त निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अल्पसंख्यकों की घोषणा का अधिकार नहीं है, यह विषय राज्य सरकार का है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 न तो केन्द्र की लिस्ट-1 में और न राज्य लिस्ट के विषयों के तहत ही आते हैं। टीएमए पाई के केस 2002 (2) एससीसी 481 में जो विवेचन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बाबत संसद को शिक्षा के बाबत कानून बनाने का अधिकार है। जबकि अधिनियम 1992 उन अल्पसंख्यकों के हेतु है जिन्हें केन्द्रीय सरकार अल्पसंख्यक घोषित करेगी और अनुच्छेद 29/30 धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का मूल अधिकार देता है और टीएमए पाई का निर्णय निर्देश देता है कि ऐसे शिक्षण संस्थाओं के मामले में केन्द्र कोई दखल नहीं देगा। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 अवैध है और साथ ही अल्पसंख्यक की परिभाषा अविवेकपूर्ण है, निरंकुश है और अधिकार शून्य होने से अवैध है। इस अधिनियम 1992 की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को जो 4% कोटा (आरक्षण) दिया है वह अवैध है। इन्द्रा साहनी के केस में जो आरक्षण के सम्बन्ध में एक अकाट्य नजीर है, उसके अनुसार भी यह आरक्षण असंवैधानिक है। उक्त नजीर पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उसके अनुसार आरक्षण पिछड़ेपन (सामाजिक उत्पीडन) के आधार पर है। यह माना गया है कि हिन्दू व गैर हिन्दू की गणना के अनुसार हिन्दू 50% से अधिक हैं और दूसरा सिद्धान्त उक्त केस में यह निर्धारित किया है कि गैर हिन्दू आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। वस्तुतः 4% मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी के केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) में है, वह तो प्रत्यक्षतः ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वयं ही अर्थ शून्य हो जायेगा। यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिये कि इन्द्रा साहनी का केस समाज के पिछड़ों, एससी व एस्सी के लोगों को समानता के स्तर पर लाने के हेतु था। किन्तु यह स्थिति उन लोगों की नहीं है, जिन्हें धारा 2(सी) की केटेगरी में अल्पसंख्यक के रूप में लिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मत प्राप्त करने हेतु कुछ धर्म के लोगों को लुभाने हेतु यह कानून लाया गया है। प्रोबीज का यह भी एक रूप है।

कर्नाटक सरकार का निर्णय कि वह सार्वजनिक कार्यों के ठेके में 4% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे जबकि एस्सी, एससी और ओबीसी को पहले ही से आरक्षण है। विभिन्न प्रकार के आरक्षण से जहां विकास होना चाहिये था वहां 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी को भी क्रिमीलेयर में स्थान नहीं दिया जा रहा है और अनुच्छेद 334 के तहत आज भी आरक्षण को समय सीमा को अप्रभाव्य नहीं माना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार सही नहीं है यह कृत्य धार्मिक भेदभाव व लुट्टिकरण का एक रूप है। अतः यह प्रावधान असंवैधानिक है।

एस्पेकम जयते!

-अतिथि सम्पादक,  
पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को सहेजे राजस्थान का स्थापना दिवस पहली बार अंग्रेजी तारीख के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जा रहा है। यह अवश्य संजोग ही माना जाएगा कि इस साल देशी और अंग्रेजी कलेंडरों के हिसाब से 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि पधारों म्हारे देस आमंत्रण के साथ राजस्थान दिवस का आयोजन महज औपचारिकता या आयोजन प्रयोजन तक सीमित ना रहकर

एक विस्तृत सोच और चिंतन का परिणाम है और यह कारण है कि राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई है जिससे केवल एक दिन की औपचारिकता ना रहकर सात दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो और आम जन से जुड़े कार्य, योजनाएं और सीधे संबंधित लोगों से संवाद कायम हो सके।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि राजस्थान दिवस एक दिन का औपचारिक आयोजन ना होकर सात दिन तक के आयोजन एक विस्तृत जनाहित से जुड़े कार्यक्रमों के साथ हो रहे हैं। 25 मार्च को बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के आयोजन के साथ आरंभ हुए इन कार्यक्रमों की कड़ी में पहले दिन ही एक किलक के साथ ही लाभार्थी महिलाओं की खालों में 375 करोड़ रु. की राशि का हस्तान्तरण हो गया। महिलाओं से जुड़े 7 विभागों की 11 योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह से एक किलक में

होने और बाड़मेर में कार्यक्रम के आयोजन से एक संदेश गया है। 26 मार्च को बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित कर 30 हजार किसानों तक 137 करोड़ रु. के अनुदान स्वीकृति के साथ ही किसानों और पशुपालकों से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और सीधा संवाद कायम करने की बड़ी पहल की गई है। राजस्थान स्थानों के अवसर पर आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में 27 मार्च को भरतपुर में अन्त्योदय कल्याण योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम और सुशासन दिवस के रूप में आयोजन किया गया है। इसी तरह से 29 मार्च को कोटा में व 30 मार्च से 31 मार्च को जयपुर में आयोजन होंगे। इस दौरान अनेक योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने के साथ ही नई नीतियों भी लाने का कार्यक्रम इस आयोजन को और अधिक उपादेय बनाएगा। यह साफ हो जाता है। इसी कड़ी में 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान के करीब 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राण्ड

ब्रेकिंग लॉजिस्टिक डेटा सेंटर और टैक्सटाइल पालिसी की घोषणा महत्वपूर्ण कार्य होंगे। दरअसल दिवस के आयोजन आयोजन प्रयोजनों के साथ महज औपचारिकता बन के रह जाना आम है। पर जिस तरह से इस बार कार्यक्रमों को इस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है जिससे सीधे प्रदेशवासियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा और सबसे खास यह कि राजस्थान स्थापना दिवस केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहकर प्रदेश के हर कोने में होने से इसका एक अलग ही संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक सोच इन आयोजनों के पीछे साफ दृष्टिगोचर होती है कि आयोजन सोद्देश्यपूर्ण और जनहित के हो। यही कारण है कि सात दिन तक आयोजन, दिन विशेष को वर्ग विशेष यथा महिला, किसान, युवा, निवेशक आदि आदि से जुड़े कार्यक्रम आयोजनों से दिन विशेष को लक्षित लाभार्थियों को लाभ का हस्तान्तरण भी आसानी से संभव हो पाता है। कार्यक्रम के बहाने दिनों में होने वाले कार्य दिन विशेष को ही हो जाता है और

यही प्रशासन को सफलता होती है। दरअसल राजस्थान दिवस कार्यक्रम सात दिवस तक आयोजनों के पीछे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की संवेदनशील, लोकहितकारी और दूरगामी सोच का परिणाम है। इससे निश्चित रूप से समूचे प्रदेश को लाभ होगा और नहीं भूलना चाहिये प्रक्रिया में चल रहे कार्य चंद समय में पूरे हो जाएंगे और आमजन में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार आमजन के हितों के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। एक दूसरी बात जब आयोजन आमजन के बीच होते हैं तो पहले ही फीड बैक के रूप में ही हो पर सरकार को कई नई जानकारी और जनहित से जुड़े बिन्दुओं की जानकारी मिलती है जो समय आने पर सरकार की योजनाओं के निर्माण और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध हो जाती है। राजस्थान सरकार का राजस्थान दिवस सात दिन के कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे संवाद का परिणाम सकारात्मक हो जाएगा।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
(वरिष्ठ लेखक)

## सभी सरकारों द्वारा किसानों के साथ इतना संगदिल व्यवहार क्यों?



महावीर सिंह

पाठकों की स्मृति में होगा कि 09 अगस्त 2020 में एक बड़ा किसान आंदोलन प्रारम्भ हुआ था। तात्कालिक कारण था तीन ऐसे अध्यादेश लाना जिन्हें कालांतर में कृषि के तीन काले कानून के रूप में जाना गया। उसी आंदोलन की निरंतरता में अपनी मांगों को लेकर पंजाब-हरयाणा के किसान खनोरी व शम्भू बाँदर पर लगातार धरने पर बैठे थे। मुख्य मांग है कि लिए कानून बनाए की उस से नीचे किसान का माल नहीं बिकेगा। अन्य मांग भी थी किन्तु वाली मांग मुख्य थी। इन आंदोलनकारियों को भी अभी हाल ही में बड़ी बेरहमी से वहां से हटाया है। सही है किसान सरकार को यह ताकत के सामने धरना प्रदर्शन जारी नहीं रख सकते थे। पर प्रश्न तो यह है कि यदि यह यथा काल था तो बैठने ही क्यों दिया? क्या यथायात सुचारु रहे इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी?

चलिए 2020-21 में लौटते हैं। अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि आखिर बिना हित धारकों से व्यापक चर्चा किये, बिना लोकसभा में विस्तार से चर्चा कराए, आनन-फानन में यह कानून किन सलाहकारों की सलाह पर लाए गए। आखिर में, 700 किसानों की शाहदत के बाद, 19 नवम्बर 2021 को, इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ी। कितना अच्छा होता यदि बिना इतने किसानों की शाहदत के ही प्रधानमंत्री जी, अफर्नलन की शुरुआत में ही ऐसा कर देते। यद्यपि जानकारों का मानना है कि कानून के अध्यादेश लाने के कारणों का तो पता नहीं किन्तु कानून वापस लेने का तात्कालिक कारण उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाव था ऐसा सामान्यतः सभी मानते हैं। भाजपा उत्तरप्रदेश चुनाव पहले की तुलना में कम सीटों के साथ चुनाव जीत गई। चुनाव परिणाम आते ही, अति उत्साही भाजपा समर्थकों ने कह दिया कि यह सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए तीन कृषि कानूनों के प्रति समर्थन है

अर्थात् कानून किसानों के हित में थे। नोटबन्दी को भी चुनाव में सफलता के साथ ही जोड़ कर उसे उचित बताया था। नोटबन्दी के घोषित लक्ष्य, शायद ही प्राप्त हुए। कृषि कानूनों को तो स्वयं सरकार ने ही वापस लिए। नोटबन्दी व कृषि कानूनों के बाद के चुनाव केवल इन्हीं मुद्दों पर, हितधारकों यथा गरीब गुरुख, छोटे व्यापारियों-उत्पादनकर्ताओं अथवा किसान मतदाताओं के बीच का ही जनमत संग्रह नहीं था। चुनाव में अनेक अन्य मद्दे व अन्य सभा गणों के मतदाता भी होते हैं। यथा मंहगाई, बेरोजगारी, शोषितव्यवस्था, जात-विवाद, कंडीटेड की व्यक्तिगत छवि व अन्य कई मुद्दे।

इसलिए चुनाव सफलता को केवल व केवल नोटबन्दी या किसानों हितों के साथ जोड़ना न्याय संगत नहीं। कोई सामान्य नागरिक आज तक यह तो स्वीकार करता नहीं कि यह दोनों कदम देश व जन हित में अत्यंत सुविचारित कदम थे। इसके विपरीत करोड़ों करोड़ों देशवासियों ने इनसे हुआ कष्ट झेला है।

चलिए इन सब बातों हटे और किसान आंदोलन की बात करें। प्रधानमंत्री जी द्वारा तीन कृषि कानूनों को यह कहते हुए वापस लिया कि किसानों को इन कानूनों के दूरगामी लाभदायक प्रभावों से संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके साथ ही किसान आंदोलनकारियों की सहित अन्य मांगों पर विचार करने व सुझाव देने के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा भी की थी।

पहले तो कमेटी का गठन ही 7 माह के न समझ में आने वाले विलम्ब के बाद हुआ। इस कमेटी में 18 सरकारी व 11 गैर सरकारी सदस्य नामित किए जाने थे। 11 गैर सरकारी सदस्यों से मात्र तीन सदस्य आंदोलनकारी किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चे (SKM) द्वारा नामित किए जाने थे। गठन को लेकर, कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर स्पष्टता के अभाव में एख्खे ने कोई सदस्य इस कमेटी में नहीं भेजे। यह कि स्पष्ट नहीं कि क्या कमेटी को एख्खे की गैरिटी के जूनू का मसौदा बनाना भी था या नहीं??

चलिए एख्खे ने कमेटी में सदस्य बनने के लिए नाम नहीं भेजे तो नहीं भेजे किन्तु कमेटी में भी 2 वर्ष, 8 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी एख्खे पर कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी। इस मामले में तो "नो दिन चले अडाई कोस वाली" कहवात चरितार्थ हुई है।

इस से यह भी सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि सरकार MSP की गांटी से सम्बंधित कानून पर, मात्र, किसानों

को उलझाए रखना चाहती है किन्तु ऐसा कानून लाने का कोई इरादा लगता नहीं, कम से कम शीघ्र तो कर्तई नहीं। चलिए अब विचार करें कि MSP की गांटी के कानून के पक्ष-विपक्ष पर विभिन्न पक्षों के क्या विचार, तर्क हैं-सरकार के सलाहकार समूह द्वारा उसके विपक्ष में दिया जाने वाले तर्क हैं कि-- किसानों की समर्थन मूल्य वसूलि सारी गजलों को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान चाहिए अगर ऐसा किया जाता है तो अन्य कार्यों व मुख्यतः विकास कार्यों के लिए बजट बचगा ही नहीं। दूसरा तर्क है कि ऐसा करने से कृषि उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खुले बाजार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। यह किसानों के लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं को बहुत मंहगे कृषि उत्पाद खरीदने को खरीदने के लिए 2

## ‘ममता बनर्जी, बांग्लादेश व म्यांमार के घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, भारत में प्रवेश के लिए’

संसद में फॉरैनर्स विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं

-अंजय रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वही दोहराया है, जो जगजिहिर है।

विदेशियों से संबंधित विधेयक पर अपने जवाब में उन्होंने शिकायत की है कि बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से आये घुसपैठियों तथा म्यांमार से आये रोहिंग्याओं को पहचान पत्र प्रदान कर दिये हैं। पहचान पत्र के साथ अवैध रूप से आये ये लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। बंगाल सरकार का व्यवहार पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तथा आम जनता की सुरक्षा के मामले में समझौता कर रहा है। शाह ने कहा कि यह विदेशी विधेयक (फॉरैनर्स बिल) लागू होने के बाद, देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों की कई स्तरों पर मॉनिटरिंग का तंत्र उपलब्ध करायेगा। यह विधेयक सुरक्षा-संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक खुफिया तंत्र भी उपलब्ध करायेंगा।

अमित शाह ने वही बात कही है, जो हमेशा से ज्ञात रही है। बंगाल सरकार राज्य में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए

■ शाह के अनुसार, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को अस्थाई रूप से रहने व छुपने के लिये स्थान देती हैं तथा फिर आइडेंटिटी कार्ड (आधार कार्ड) मुहैया कराकर देश भर में फैलने का मौका देती हैं।

■ “यह वोट बैंक बढ़ाने की रीति-नीति चौंतीस साल, वामपंथी सरकार ने भी चलाई थी तथा एक विपक्ष की नेता के रूप में ममता बनर्जी संसद में जमकर विरोध करने में सबसे आगे रहती थीं, पर, अब सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी स्वयं उस रीति-नीति का अनुसरण कर रही हैं।”

■ शाह ने इसी संदर्भ में संसद में यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार, सीमा पर फेंसिंग कराने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फेंसिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फेंसिंग का काम शुरू भी हो तो तुणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फेंसिंग का काम रोकना पड़ता है।

बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित कर रही है। त्वरित लाभ के लिए यह जो किया जा रहा है, राष्ट्र-हित के साथ चृणित समझौता है। शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने

सीमा पर बाड़ के लिए जमीन आवंटित नहीं की है। जहाँ भी बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा था, वहाँ तुणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने विरोध किया था और काम रूकवा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ

कि आज भारत-बांग्लादेश सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ संभव है।

लोग दण्ड भय मुक्त होकर बंगाल में आ रहे हैं तथा सीमा से लगे इस राज्य की जनसंख्यिकीय प्रकृति (डेमोग्राफिक नेचर) बदल रही है। इससे स्थानीय बंगालियों के हितों को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि घुसपैठिये, राज्य सरकार तथा तुणमूल कांग्रेस के गुन्डों की मदद से, यहाँ रहने वाले बंगालियों की जमीन छीनकर अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को बसाने में उनकी मदद कर रहे हैं।

अवैध घुसपैठियों से अपना वोट बैंक बनाने और बढ़ाने की यही रणनीति राज्य की कम्युनिस्ट सरकारों ने अपनायी थी। वामपंथी मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में, कम्युनिस्टों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था।

विडम्बना देखिये, इन्हीं ममता बनर्जी, जब वे विपक्षी नेता थीं, ने अवैध घुसपैठियों को चुपचाप आने देने की वामपंथी मोर्चे की चाल का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने उस समय बंगाल में हो रहे अवैध प्रवेश का संसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई को नहीं दी जाएगी

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली एबीवीपी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजी ने पेपर लीक की बात मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करावई जा चुकी है, वहीं एसओजी ने भी मामले में जाँच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पद्मेश मिश्रा की ए.ए.जी. पद पर नियुक्ति के विरुद्ध अपील दायर

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने इस मामले की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एडीशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.), पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति के खिलाफ अपील दायर की गई है। इस अपील में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा 4 फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति को उचित ठहराया गया था। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया था।

इस अपील की पहली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल के समक्ष 3 मार्च को हुई थी, परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य खण्डपीठ को सौंप जाने के आदेश दिए थे और उन्होंने स्वयं इस मामले को सुनने के लिए असमर्थता बताई थी।

यह मामला न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समदड़िया को आदेश दिए कि वे अपील की प्रति राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ

■ जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील समदड़िया का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

■ नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य बताया गया है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

अधिवक्ता और ए.ए.जी. भरत व्यास को सौंपे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है।

जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वादनीति 2011 में ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूनतम अनुभव के संबंध में कोई मापदंड निर्धारित नहीं था, केवल यह कहा गया था कि सरकारी वकील बनने के लिए 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, परन्तु वर्ष 2018 की वादनीति के तहत, ए.ए.जी. की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के पास कम से कम

10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पद्मेश मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लॉयअर नियुक्त होने के तीन दिन के भीतर राजस्थान सरकार ने वादनीति में संशोधन किया (जो बिलकुल भी स्पष्ट और नीतिगत नहीं है) और फिर पद्मेश मिश्रा को संशोधित नियम के तहत ए.ए.जी. घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने का अधिकार देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अन्य धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनुभव के मापदंड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सबसे पहले लाइफ इंश्योरंस

आजीवन गारंटीड मासिक आय की योजना बनायें हमारे बढ़े हुए वार्षिकी दरों के साथ एक वर्ष की न्यूनतम स्थगितकरण अवधि के बाद वार्षिकी शुरू हो सकती है

2 वर्ष

3 वर्ष

4 वर्ष

5 वर्ष

अधिकतम स्थगितकरण अवधि वार्षिकी योजना के लिए

ऑनलाइन भी उपलब्ध

निश्चित वार्षिकी दरें पॉलिसी के प्रारंभ से

अनेक वार्षिकी विकल्प

बढ़ता हुआ मृत्यु लाभ आस्थगन अवधि के दौरान

हमारा बॉट्सपप नं. 8976862090

कहिए 'Hi'

हाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC

विजिट करें: licindia.in

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/विजिट करें www.licindia.in या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LICPI/2024-25/23/HIN

9 से 5 की नौकरी को करें अलविदा, बने म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर।

अपने नए सफर की शुरुआत के लिए

www.mfdkareinshuru.com

करें शुरू?

Mutual Funds DISTRIBUTOR

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।





## सार-समाचार

### क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन

**भरतपुर।** भरतपुर साइकिल क्लब की ओर से डे नाइट क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बीसीसी टाइगर टीम विजेता रही। क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीसीसी पैथर और बीसीसी लायन टीम के बीच हुआ। लायन टीम ने पहले खेलते हुए 114 रन बनाए, जिसके जवाब में पैथर टीम के खिलाड़ी 104 रन ही बना पाए। बाद में फाइनल मुकाबला बीसीसी लायन और बीसी टाइगर के बीच हुआ। बीसीसी लायन ने पहले खेलते हुए 104 रनों का स्कोर खड़ा किया। जिसके जवाब बीसी टाइगर ने हाफ टाइम के बाद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर एक बॉल में ही 105 रन बना लिए। हाफ सेंचुरी सार्थक अरोड़ा में लगाई। बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान फुटबाल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद पाल सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैम ऑफ द मैच सार्थक अरोड़ा, वेस्ट बल्लेबाज कुणाल गुप्ता और ब्रेस्ट बॉलर गौरव जैन को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अरविंद पाल सिंह ने कहा कि इस तरह की आयोजन सराहनीय और जरूरी है। इससे आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। कोरोना के बाद यह साबित हो चुका है कि प्रोफेशनल व्यक्तियों और व्यापारियों को आउटडोर एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। इससे इंटरनेट युग में जी रही नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष पंकज गोयल संरक्षक लोकेश अठावाल, नवीन पाराशर सहित कार्यक्रम में सहयोगी रहे सुनील कंसल, गौरव जिंदल, लोकेश ज्वाला जी, योगेश स्वप्नील जीवन जैन सुमित अरोड़ा आदि को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिलाओं के लिए साइकिल रेस प्रतियोगिता जल्द आयोजित करने की घोषणा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए।

### विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान

**भरतपुर, (निर्स)।** फस्ट राजधानी जुडो चैंपियनशिप में राजस्थान भरतपुर की कैडेट गर्ल्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता। दिल्ली में आयोजित हुई राजधानी जुडो चैंपियनशिप 2025 में कैडेट वर्ग की गर्ल्स टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भरतपुर शाला क्रीडा संगम की खिलाड़ी मनोरमा बोहरा ने फाइनल मैच में मणिपुर की खिलाड़ी को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं भूमि सिंह ने महाराष्ट्र दिल्ली जम्मु कश्मीर राज्य की खिलाड़ियों को हराकर लीग के फाइनल में प्रवेश कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों का सम्मान भरतपुर में नदबई विधायक कुं जगत सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी सरीना फाउंडेशन की अध्यक्ष सोमाया सिंह द्वारा किया गया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इन सभी खिलाड़ियों को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जितने की शुभकामनाएं दी। शाला क्रीडा संगम में प्रैक्टिस करने वाले 8 खिलाड़ियों को सरीना फाउंडेशन द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है इन खिलाड़ियों ने 2024-25 में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भरतपुर और राजस्थान का नाम रोशन किया है। इस दौरान सतेन्द्र गुड्डू परमिन्द्र तंवर शैलेंद्र सिंह खिलाड़ी अनुराग भानु जाजिया अक्वी लावण्या भूमि मनोरमा और मौजूद रहे। कोच जुडो की पूजा देशवाल ने बताया कि भरतपुर जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है यहाँ के खिलाड़ियों को इसी तरह सपोर्ट और अच्छी प्रैक्टिस अच्छा टाउंड मिल जाए तो भरतपुर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेंगे ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी।

### विद्यार्थियों ने किया शैक्षिक भ्रमण

**भुसावर/भरतपुर, (निर्स)।** पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलैना के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों ने 27 मार्च 2025 गुरुवार को कृषि महाविद्यालय भुसावर का शैक्षिक भ्रमण किया। महाविद्यालय के डीन डॉ. उदय भान सिंह ने विद्यार्थियों को नींबू, आम, अमरूद, ऑलवा आदि बगीचों का भ्रमण कराया तथा विभिन्न फलदार बगीचों की समस्याएं एवं उनके समाधान बताये। डॉ. उदय भान सिंह ने कहा कि यदि किसान अपने उत्पाद को बाजार में सीधे बेचने के बजाय उसे प्रोसेसिंग करके बेचे तो दो से तीन गुना लाभ बढ़ाया जा सकता है। जैसे गेहूँ का कलिया या मैदा, आम व नींबू का अचार, अमरूद से जैली, फलों के स्क्वश, जैम, मुरब्बा, बेर की केचुप, टमाटर का सॉस या कैचअप आदि बनाकर बेचने से कुल लाभ बढ़ता है तथा डामोनी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में विज्ञान की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में कुल कृषि उत्पादन के 5 प्रतिशत हिस्से की प्रोसेसिंग होती है, जबकि विकासित देशों में यह 95 प्रतिशत तक है। अतः युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, इससे फसलों के कटाई पश्चात होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है तथा कृषि उत्पादों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। इस अवसर पर हलैना विद्यालय के प्रधानाचार्य निरमल सिंह कसाना, कृषि व्याख्याता अभय सिंह मीना सहित अन्य स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे।

### श्री राम शोभा यात्रा हेतु बैठक

**भरतपुर, (निर्स)।** आज रूपलापायसा मोहल्ला भरतपुर में श्रीराम शोभा यात्रा के उपाध्यक्ष कौशलेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रीराम शोभा यात्रा व कलश यात्रा में महिलाएं व पुरुषों की अधिक से अधिक संख्या शामिल होना का आ आ किया। श्रीराम कथा की कलश यात्रा 29 मार्च प्रातः 9 बजे श्रीलक्ष्मण मंदिर से प्रारंभ होकर श्री विहारी जी मन्दिर कथा स्थल पर पहुंचेगी। भगवान श्रीराम जी की शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2025 को अनाज मंडी कुम्हरे गेट से होते हुए बाजार से गुजरते हुए कॉलेज टाउंड पर महा आरती पश्चात विसर्जन होगा। शोभायात्रा को भव्य दिव्य बनाने में शहर व जिले के सभी युवा महिला पुरुष कलश व शोभा यात्रा में में भाग लेकर परमसौभाग्य प्राप्त करें। प्रत्येक सदस्य रामदूत बनकर शोभायात्रा को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर पुण्य प्राप्त करें। मोहल्ले से अधिकाधिक भागीदारी की जिम्मेदारी नीरज शर्मा व उनकी धर्मपत्नी को सौंपी गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्त उपनिदेशक व सर्व शक्ति मित्र मंडल जिलाध्यक्ष नेमीचंद मुद्गल भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर जा जिलाध्यक्ष रविन्द्र मोहन शर्मा अन्नपूर्णा रसोई संचालक विष्णुदत्त शर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ईश्वरी प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा अशोक कुमार साहस सेवानिवृत्त थानेदार प्रभूदत्त कटारा सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष दिनेश चंद जघीना तिलक नगर ब्राह्मण समाज वरिष्ठ सदस्य पंडित वनवारी लाल मदन मोहन अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र जैती देवेन्द्रमोहन तिवारी लाल चंद एल आई सी प्रमाणिक बाबूलाल शर्मा एवम मोहल्ले के महिलाएं व पुरुष उपस्थित हुए।

### परीक्षा आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन

**करौली, (निर्स)।** राजकीय महाविद्यालय करौली में गुरुवार को परीक्षा विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय परीक्षा आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. विश्राम लाल बैक्वा ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में विद्यार्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार तनावों से बचने की सलाह दी। परीक्षा प्रभारी रफीक अहमद ने विद्यार्थियों को नई शिक्षा पद्धति के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किये। इस अवसर पर आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. सीताराम खण्डेलवाल ने विद्यार्थियों को एनईपी 2020 के अनुसार परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित परिवर्तन के बारे में अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को सैमिस्टर सिस्टम की विस्तृत जानकारी, प्रदान की। इस अवसर पर महाविद्यालय के नवाचार एवं कौशल विकास प्रकौष्ठ प्रभारी डॉ. प्रीतम सिंह मीना ने विद्यार्थियों के साथ अपने परीक्षा से सम्बन्धित अनुभव साझा किये तथा विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका में लिखने की कला के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी परीक्षा से सम्बन्धित जिज्ञासा को उजागर करते हुए प्रश्नों की। कार्यक्रम का मंच संचालन विश्राम सिंह मीना ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

### विधायक डॉ गर्ग ने की जनसुनवाई

**भरतपुर, (निर्स)।** पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ सुभाष गर्ग ने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन रणजीत नगर स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेन्द्र सिंह से विधायक डॉ गर्ग की आत्मीय मुलाकात हुई और भरतपुर के विकास और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर डॉक्टर गर्ग द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री का स्वागत सम्मान किया गया। जन सुनवाई में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को विधायक डॉ. सुभाष गर्ग के समक्ष रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

# विधायक गुर्जर ने पूजा-अर्चना कर किया भंडारे का शुभारंभ

**करौली, (निर्स)।** करौली जिला मुख्यालय पर इन दिनों भक्तों कि ओर से कैलामाता कि पदयात्रा कर रहे यात्रियों के लिए भोजन भंडारे संचालित हो रहे हैं जिनमें से एक भोजन भंडारे का करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कैलामाता कि पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया।

मां कैलामाता भक्त मंडल कि ओर से हाथीघटा स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में तीन दिवसीय विशाल भंडारे का शुभारंभ हुआ भंडारा संचालक मंडल के गोविंद बजाज ने बताया कि प्रातः करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर एवं नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने कैलामाता के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वल कर भंडारे का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया इस दौरान कन्या लांगराओ को जीमन कराया गया एवं भक्तों को हलवा,पूरी,सब्जी की प्रसादी वितरणी की गई वही दोपहर के समय तेज धूप और ममी के बीच पैदल चल रहे पदयात्रियों को शीतल टंडाई का वितरण किया गया वही रात्रि के समय राजमा,चावल,पूड़ी,चपाती का भोजन कराया गया इस दौरान वस्त्र व्यापार संघ

## बिजली कनेक्शन का

**करौली, (निर्स)।** विद्युत विभाग का करौली नगर परिषद पर करीब 2 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है जिसको लेकर विभाग ने कार्यवाही करते हुए परिषद कार्यालय सहित सीवेज लाइन के तीन विद्युत कनेक्शन को काटकर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी। इन दिनों करौली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में विद्युत विभाग को ओर से माच माह में विद्युत बकाया दरी से राशि वसूली का अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी टामोनी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से बकाया राशि वसूली कर रहे हैं वही राशि जमा नहीं करने पर उनके ट्रांसफार्मर उतारकर विद्युत आपूर्ति बंद की जा रही है विद्युत विभाग के सहायक अभियंता (अप्रम) ललित बाबुर ने बताया कि करौली नगर परिषद पर भी करीब 2 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है कई बार उन्हें राशि जमा करने के लिए पत्र व नोटिस भी दिए गए हैं लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई जिस पर बुधवार को कार्यवाही करते हुए नगर परिषद कार्यालय सहित सीवेज लाइन के तीन विद्युत संबंधी कनेक्शन को काटकर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है।

# समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की पहचान : कसाना

**भरतपुर, (निर्स)।** राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से भरतपुर आए शहर ब्लॉक कांग्रेस के प्रभारी बबलू कसाना ने यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर कहा कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की पहचान है। जाजम विधान से लेकर झंडा फहराने तक का काम कार्यकर्ता ही करता है।

शहर ब्लॉक अध्यक्ष दयाचंद पचौरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीसीसी जिला एवं शहर पदाधिकारियों ने प्रभारी बबलू कसाना का सूत की माला एवं कांठोस पार्टी का पटक का पहनकर स्वागत किया। शहर



करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर (बीच में) का स्वागत करते भंडारा संचालक मंडल।

से जुड़े कैलाश बजाज,अमर सिंह तंवर,लेखराज,महेश बजाज,गुड्डू तिरपाल वाले, संजू कंयूटर,आशीष गुप्ता,लहरी बजाज,संजू बजाज,वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष विक्की बजाज,रवि जिंदल,गोपाल गुप्ता के अलावा कई अन्य कपडा व्यवसाई और

भामाशाह उपस्थित रहे। इसके अलावा बाल्मिक आश्रम पर डॉ. गोविंद गुप्ता उनकी पत्नी अनीता गुप्ता के नेतृत्व में चाय और नाते कि पदयात्रियों को व्यवस्था कि गई इस दौरान पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश गुप्ता डॉ. गीव लहरी गुप्ता आदि उपस्थित थे वही

स्टेडियम के समीप ओमप्रकाश शर्मा भगत कि ओर से पूड़ी सब्जी कि प्रसादी लगाकर पदयात्रियों को वितरण कि गई वही शहर के करीब दो दर्जन स्थानो पर पदयात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, शीतल पदार्थ पिलाकर भंडारे लगाये जा रहे है।

## जिले में 44 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों का किया सम्मान

**करौली, (निर्स)।** विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परेडवाल के आतिथ्य में मेडिकल कॉलेज सभागार में किया गया।

अभियान अंतर्गत निर्धारित 6 मापदंडों का जिन ग्राम पंचायतों में श्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है उन 44 ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा जमूरा और लेदिया ग्राम पंचायत को पिछले वर्ष टीबी मुक्त ग्राम पंचायत होने पर महात्मा गांधी की कांस्य स्टेचू प्रदान की गई।सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एडीएम परेडवाल ने कहा कि टीबी की बीमारी से बचाव के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले आहार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव को टीबी से मुक्त करने में सरपंचों की भूमिका अहम है, जागरूकता के

लिए और प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे आगामी वर्षों में हम टीबी मुक्त पंचायत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परेडवाल के आतिथ्य में मेडिकल कॉलेज सभागार में किया गया। अभियान अंतर्गत निर्धारित 6 मापदंडों का जिन ग्राम पंचायतों में श्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है उन 44 ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा जमूरा और लेदिया ग्राम पंचायत को पिछले वर्ष टीबी मुक्त ग्राम पंचायत होने पर महात्मा गांधी की कांस्य स्टेचू प्रदान की गई।सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए एडीएम परेडवाल ने कहा कि टीबी की बीमारी से बचाव के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना होगा और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले आहार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव को टीबी से मुक्त करने में सरपंचों की भूमिका अहम है, जागरूकता के

प्रमाण के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सरपंचों का जो सहयोग मिला है वह आगे भी मिलता रहे। उन्होंने निश्चय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायताार्थ पोषण किट उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ कपेंद्र कुमार द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की अंतर्गत 25 फरवरी से 24 मार्च तक आयोजित गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा जागरूकता माध्यमों की जानकारी को साझा करते हुए प्रचारमर्मां द्वारा टीबी मुक्त ग्रामों में सहयोग की आवश्यकता जताई। इस दौरान मंच संचालन जिला कार्यक्रम ऑफिसर आयुषीष पांडे द्वारा किया गया एवं अभिवादन संबोधन जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ गोविंद गुप्ता द्वारा दिया गया। समारोह में जिला कार्यक्रम समन्वयक- आईईसी लखन सिंह लोधा, बीसीएमओ, यूएमएफपीए प्रतिनिधि मनोज जांकिंड सहित सरपंच और टीबी क्लीनिक के कार्मिक मौजूद रहे।

## गुम हुए मोबाइलों को लौटाया

**करौली, (निर्स)।** मार्च (नि.सं.) करौली कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्यवाही करते हुए 22 लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन उन्हें बुलाकर कोतवाली में सुपुर्द किये। कोतवाली थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि आपका मोबाइल आपके हाथ करौली पुलिस है आपके साथ कि भावना में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बुजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत करीब चार लाख रुपये कि बाजार कीमत के 22 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किये उन्होंने बताया कि गुम हुए मोबाइल मालिकों को जब मोबाइल सुपुर्द किया।

# केलादेवी के पदयात्रियों की सेवा में जुटे हिण्डौन क्षेत्र के लोग

**हिण्डौन सिटी, (निर्स)।** राजराजेश्वरी केलादेवी माता के चैत्रमास मेले में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में पदयात्रियों की भक्तिगर्भी की गुँज के साथ हो रही आवक और जगह जगह लगे पांडालों, भंडारों से पूरा शहर भक्तिमय बना हुआ है। भारत विकास परिषद, शाखा हिण्डौन सिटी ने शीतल पेयजल व मेडीकल फर्स्ट एड का पांच दिवसीय पांडाल लगाकर इसमें पहलीबार सहभागिता की है।

शाखा सचिव दीनदयाल सिंघल ने बताया कि प्रतिवर्ष इस मेले में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लाखों पदयात्री माता कैलादेवी के दर्शन करने पहुँचता है इस वर्ष भी भारी संख्या में पदयात्रियों की आवक बनी हुई है मातारानी के दरबार में पहुँचने वाले भक्त जय माता दी, जय माता दी के नारे लगाते हुए आस्था लेकर बढ़े चले जा रहे हैं चारों तरफ माता के भजनों की गुँज है। शहर में मुख्य मार्ग पर पांडाल लगाकर भिन्न भिन्न सेवादातों द्वारा खाने पीने, चाय नाश्ता, स्नान, विश्राम, मेडीकल सुविधाओं की व्यवस्थाएँ रखी गई हैं, शहरवासी हजारों लोग तन, मन, धन से इसमें अपनी सहभागिता करके पांच दिन तक पदयात्रियों को बेहतर सुविधाएँ करने में जुटे हुए हैं।



भारत विकास परिषद की ओर से पदयात्रियों को भंडारा लगाकर की जा रही है सेवा।

शाखा अध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि परिषद द्वारा इस लखड़ी मेले में पदयात्रियों के लिए 24 से 28 मार्च तक बयाना मोड स्थित बसन्त होटल के नीचे शाखा सदस्य आलोक सोलंकी के सहयोग से स्वच्छ व शीतल पेयजल व परिषद द्वारा मेडीकल फर्स्ट एड सुविधा का पांडाल लगाया है। शाखा सदस्यों के सहयोग से पदयात्रियों को निर्मल जलसेवा के साथ मंगलवार को नमकीन

छाछ, बुधवार को प्रातः चाय टोस्ट नाश्ता, सांय को शर्बत, गुरुवार को प्रातः चाय टोस्ट नाश्ता, दोपहर में नमकीन छाछ एवम् अपरान्ह चौरा, पपीता, अंगूर आदि फलों का वितरण किया, शुक्रवार को समापन के दिन वितरण किया जाएगा। सचिव ने बताया कि पेयजल, दवाइयाँ, छाछ, चाय टोस्ट नाश्ता, शर्बत व फल वितरण में परिषद के निरंजन शर्मा, सुबोध जैन, देवेन्द्र

शर्मा, पंकज जैन, अशोक गर्ग, मुकेश जैन, उमेश शर्मा, पवन ऐरन, योगेश बराराम, अशोक भगत, राजेन्द्र बजाज, योगेश गुप्ता (कम्प्यूटर), मांगीलाल गर्ग, राकेश गुप्ता, मोहित मित्तल, ओमप्रकाश गुप्ता दिंडोरा, सुनील अग्रवाल, डॉ पीयूष गोयल, अशोक मोदी, अनिल बाँबी, डॉ मनोज गर्ग, वीरेंद्र जैन, प्रवीण गोयल, राकेश गुप्ता (नवीन), आदि मौजूद थे।

## सार-समाचार

### धोखाधड़ी के मामले में एक गिरफ्तार

**करौली, (निर्स)।** थानाधिकारी अध्यात्म गौतम पुणिय पुलिस जाप्ता द्वारा पुलिस थाना कोतवाली करौली के अधियोग संख्या 902025 में फर्म मैसर्स बाबू भाई रसोद भाई के ट्रेडमार्क व समान कॉपीराइट का धोखाड़ी उपयोग कर बाबूभाई रसोद भाई के नाम से बीडी बनाकर बेचने के मामले में मुस्लिम मोहम्मद उवेश खान पुत्र श्रु अब्दुल समी 30 वर्ष मुसलमान निवासी नौबीकिया मोहल्ला जामा मस्जिद बोलीखार करौली थाना कोतवाली करौली को दस्तवाब किया और प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी अनुज शुभम आरपीएस लाधिकारी करौली द्वारा गिरतार किया गया जिसे आज न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर अनि अनुसंधान हेतु दिवस का पी.सी. रिमांड पर लिया गया है।उन्होने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली करौली पर प्रथम दृष्टी रुखशार अहमद पुत्र बाबू निवासी शिकारगंज चैराहा मंडरायल रोड करौली ने एक प्रार्थमिकी इस आशय कि दर्ज करायी कि प्राधी कि अनुमति के बिना प्राधी को बाबू भाई रसोद भाई निर्मित बाबू छाप बीडी के ट्रेडमार्क व समान कॉपीराइट का बिना अनुमति के उपयोग कर मोहम्मद उमेश खॉन अब्दुल समी, मोहम्मद हासिम व उजैर निवासी बोलीखार करौली द्वारा दुर्भीयपूर्ण इरादे से अपने व्यापक व्यवसाय के माध्यम से प्रामक रूप से समान कॉपीराइट अपनाकर फर्म के ट्रेडमार्क बाबू भाई से मिलता प्रतियोगिता बाबू भाई समान लोगो समान संरचना नजर बीडी का निर्माण किया है जिसके परिणामस्वरूप बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जिस मामले मे पुलिस ने कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार किया।

### रात्रि चैपाल में सुनी परिवेदनाएं

**करौली, (निर्स)।** आमजन की समस्याओं की सुनवाई व उनके त्वरित निस्तारण के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल की अध्यक्षता में बुधवार को टोडाभीम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत किखावाडा में रात्रि चैपाल के दौरान जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त एवं लिम्बित प्रकरणों का 15 दिन के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परिवादिियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। जिसे आमजन को अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान कुल 22 परिवाद प्राप्त हुए। जिनमें सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित तीन परिवाद, विद्युत विभाग से संबंधित चार परिवाद, जनस्वास्थ्य अधिकारिकी विभाग के दो परिवाद, पंचायती राज विभाग के तीन परिवाद, राजस्व विभाग से संबंधित नौ परिवाद व श्रम विभाग से संबंधित एक परिवाद का मौके पर निस्तारण किया गया। जिन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आमजन को लाभान्वित करवाने के निर्देश प्रदान किए। रात्री चैपाल के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में परिवादी उपस्थित रहे।

### अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड शुरू

**गंगारपुर सिटी, (निर्स)।** कैलादेवी का लखड़ी मेले के शुरू होने के साथ ही दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगारपुर सिटी स्टेशन पर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। यह मेला 15 अप्रैल तक चलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रोडवेज स्टैंड बनाया गया है। कोटा मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति से यहाँ 30 बसों का संचालन होगा। यह सेवा 15 अप्रैल तक 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जीआरपी के 30 और आरपीएफ के 20 जवान तैनात किए गए हैं। हिंडौन आगर के मुख्य प्रबंधक जगतेंद्र सिंह और मेला अधिकारी विष्णु कुमार ने बताया कि गंगारपुर सिटी से कैलादेवी तक का क्रिया 25 रुपए निर्धारित किया गया है। पिछले साल यह क्रिया 35 रुपए था। स्टेशन प्रबंधक कल्याण लाल मीना के अनुसार, फ्लेटफॉर्म एक और दो पर नए शौचालय बनाए गए हैं। मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रहती है। जयपुर मुख्यालय ने कैलादेवी मेला स्पेशल बसों का रूट चार्ट तैयार कर लिया है।

## गणगौर महोत्सव में महिलाओं ने लिया भाग

**गंगारपुर सिटी, (निर्स)।** अखिल भारतीय खण्डेलवाल सुमधुरा सखी सहेली मंच के तहत रंगीला राजस्थान व सनातन संस्कृति की पहचान गणगौर महोत्सव का आयोजन अत्यधिक के आवास पर रखा गया। अध्यक्ष कुशला खूटेडा वर्षा नाटाणी ने बताया कि सभी बहने हमारी पारंपरिक परिधान चुनरी व पचरंगा पहन कर आईं। कार्यक्रम की शुरुआत मां पार्वती व शिव जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर गणगौर से संबंधित गेम वह प्रश्नोत्तरी रखी गईं। वहीं गणगौर के गीतों पर रंगारंग डांस की प्रस्तुतियां दी गईं। सभी जीतने वाली बहनों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी से आग्रह किया गया कि अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी की भी व्यवस्था जरूर करें। इस मौके पर पूजा गुप्ता, कौशल्या गंगावर, सीमा, मनीषा डांस, अंसुम डांस, संतोष, उर्मिला डांस, ममता डांस, विनोयता खूटेडा, रुचि, कुशुम सांमरिया, मधु, कृष्णा ठाकुरिया, अलका टोडवाल, ज्योति, सुमन दुसाध आदि उपस्थित रहे।

### कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न

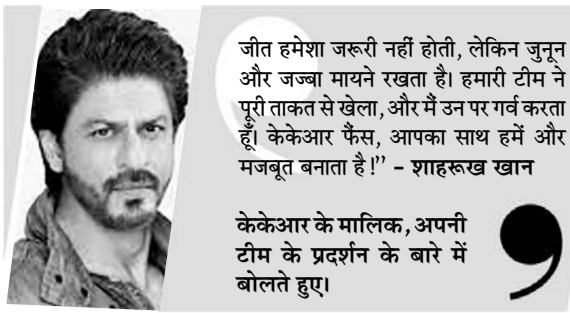
**गंगारपुर सिटी, (निर्स)।** गुरुवार को गंगारपुर सिटी और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक की जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में उनके निवास पर आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष गुर्जर ने नव संस्कार और हिंदू नववर्ष पर जिले के प्रत्येक मंडल में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के वन नेशन, वन इलेक्शन विचार पर शीतल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटने का आ आ किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। 2 अप्रैल को उपमुख्यमंत्री दिया कुमार के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। होटल द पर्ल, जयपुर बाइपास पर आठों मंडलों के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के निर्देश दिए गए। कार्यकर्ताओं ने 3000 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रारोस दिलाया। बैठक में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष धनसिंह मावई, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामसिंह खटाना, पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल, सभापति शिवरतन अग्रवाल और प्रधान मंजू गुर्जर सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री उदयसिंह गुर्जर ने किया।

### अयोध्याधाम के लिए यात्री रवाना

**गंगारपुर सिटी, (निर्स)।** शुक्रवार को डीएस रूप के संस्थापक ईंजि. उमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन की यात्रा का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन डीएस रूप द्वारा 250 वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया एक पुनीत कार्य है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को रामलला के दर्शन का अवसर प्रदान करना है। इस यात्रा का आरम्भ डीएस साईंस एकेडमी के समीप स्थित जैन नर्सिया की बगीची नर्सिया कॉलोनी से होगा। यह शोभा यात्रा सायं 6 बजे धूम-धाम से रेलवे स्टेशन गंगारपुर सिटी जाएगी जहाँ से वरिष्ठ नागरिक अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पूर्व में भी 21 मार्च को 250 वरिष्ठ नागरिकों के प्रथम दल ने अयोध्या में रामलला, हनुमान गढ़ी दर्शन व सस्यू स्नान कर अपनी यात्रा को पूर्ण कर लिया है। ईंजि. शर्मा ने बताया कि उन्होंने जो 500 लोगों को निःशुल्क यात्रा करवाने का जो संकल्प लिया था वह आज श्रीयाम जी की कृपा से पूरा होना जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह भगगो प्रान्त संघ चालक व कार्यक्रम के अध्यक्ष गंगारपुर सिटी संघ चालक डॉ. मनोज जैन एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दीपक भाई साहब जिला प्रचारक सवाई माधोपुर रहेंगे।

### जुआ खेलते तीन गिरफ्तार

**गंगारपुर सिटी, (निर्स)।** पुलिस थाना उदई मोड ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गुलकंदी स्कूल के सामने खादी भंडार के पीछे प्रसाद से तीन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर जिले में जुआ और सट्टे के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरी एवं वृत्ताधिकारी सतराम मीना के निरीक्षण में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम को मुखबिर से सूचना मिली। सब इम्पेक्टर कमल प्रसाद की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।



जीत हमेशा जरूरी नहीं होती, लेकिन जुनून और जज्बा मायने रखता है। हमारी टीम ने पूरी ताकत से खेला, और मैं उन पर गर्व करता हूँ। केकेआर फैस, आपका साथ हमें और मजबूत बनाता है। - शाहरुख खान

केकेआर के मालिक, अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए।



## खेल जगत

### आज का खिलाड़ी



आईपीएल 2025 के छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले ही राजस्थान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन यशस्वी जायसवाल ने टी-20 क्रिकेट में एक बड़ा धमाका कर दिया। जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ मैच में 24

गेंद पर 29 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने टी-20 करियर में 3000 रन पूरे कर लिए। ऐसा कर उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जायसवाल टी-20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं।

### यशस्वी जायसवाल

राष्ट्रदूत, हिण्डौन सिटी 28 मार्च, 2025 5

### लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाजी करना

#### फायदेमंद रहा : डिकॉक

नई दिल्ली, 27 मार्च। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में नाबाद 97 रन की पारी खेल कर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाने वाले सलामी बल्लेबाज विवेकन डिकॉक ने कहा कि उनके लिए मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहा। डिकॉक ने 61 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाकर केकेआर को 17.3 ओवर में जीत के लिए मिले 152 रन के लक्ष्य के पार पहुंचा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच डिकॉक ने पुरस्कार समारोह में कहा, "यह मेरा दूसरा मैच है, हमारे लिए यह अच्छा रहा कि हमने बाद में बल्लेबाजी की। एक विकेटकीपर के रूप में मुझे विकेट परखने का मौका मिला और मैं बल्लेबाजी करते समय उसके अनुसार सामंजस्य बैठा सका।" उन्होंने कहा, "मैं जानता हूँ कि आईपीएल बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ हमारे लिए मैच जीतने की कोशिश की।" दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व कप्तान ने कहा, "यह बड़े स्कोर के लिए उपयुक्त विकेट नहीं था, गेंद टर्न ले रही थी और रुक कर आ रही थी। यह सपाट विकेट नहीं था, यहां रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था।" केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने डिकॉक के साथ जीत का श्रेय टीम के स्पिनरों को दिया। उन्होंने कहा, "हमने बीच के ओवरों में दो स्पिनरों को गेंदबाजी कराई। सुनील नारायण की जगह मोईन अली खेले और उन्होंने अच्छा किया।"

### श्याम लाल कॉलेज की वार्षिक खेल मीट का आयोजन आज

नई दिल्ली, 27 मार्च। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज मैदान में शुक्रवार को छात्र और छात्राओं के वर्ग की 'वार्षिक खेल मीट 2024-25' का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज के खेल समिति के संयोजक वीरेंद्र सिंह जग्गी के अनुसार, वार्षिक खेल मीट 2024-25 के छात्रों के साथ-साथ शिक्षक और कॉलेज के गैर-शिक्षण स्टाफ भी भाग लेंगे। श्याम लाल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. रबी नारायण कर 'वार्षिक खेल मीट 2024-25' के मुख्य अतिथि होंगे। लड़कियों के वर्ग में छात्रों के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में दौड़ आयोजित की जाएगी। लड़कों में वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर में दौड़ होगी। इसके अलावा शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए कार्यक्रमों को 45 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक के दो आयु समूहों में आयोजित किया जाएगा। लेमन रेस और न्यूजिकल चेंबर स्पर्धा भी होगी।

### चोटिल लैथम पाक के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से हटवाए

वेलिंग्टन, 27 मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान टॉम लैथम चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गये हैं। लैथम को इस सप्ताह दाहिने हाथ में चोट लगी थी। प्रशिक्षण के दौरान लैथम के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि एक्स-रे रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि हुई है। लैथम की गैरमौजूदगी में माइकल ब्रेसवेल टीम की कप्तान संभालेंगे जबकि हेनरी निकोलस को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्ट्रीड ने कहा, सीरीज की पूर्ण संख्या पर कप्तान टॉम लैथम का चोटिल होना निश्चित रूप से निराशाजनक है और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले माइकल के साथ टीम सुरक्षित हाथों में है।

# लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया

हैदराबाद, 27 मार्च। शार्दूल ठाकुर (चार विकेट) की घालक गेंदबाजी के बाद निकोलस पूरन (70) और मिचेल मार्श (52) की अर्धशतकीय विस्फोटक पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के सातवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 23 गेंदों शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के 190 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज एडन मारक्रम (एक) का विकेट गंवा दिया। उन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये निकोलस पूरन ने मिचेल मार्श के साथ ना केवल पारी को संभाला दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रन भी बटोरें। दोनों



बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी हुई। यह आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दूसरे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। नौवें ओवर में पैट कर्मिस ने निकोलस पूरन को पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। निकोलस पूरन ने 26 गेंदों में छह चौके और छह छक्के लगाते हुए (70) रनों की विस्फोटक पारी खेली। 11वें ओवर में कर्मिस ने मिचेल मार्श को भी अपना शिकार बना लिया। मिचेल मार्श ने 31 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाते हुए (52) रन बनाये। चौथे विकेट के रूप में आयुष बंदोनी (छह) रन आउट हुये। कप्तान ऋषभ पंत (15) रन बनाकर आउट हुये। उन्हें हर्षल पटेल ने आउट किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16.1 ओवर में 193 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया। अब्दुल समद ने आठ गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते

हुए (नाबाद 22) रन बनाये। डेविड मिलर (नौ) रन बनाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कर्मिस ने दो, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल और एडम जम्पा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मात्र 15 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिये। अभिषेक शर्मा (छह), इशान किशन (शून्य) को शार्दूल ठाकुर ने आउट कर शुरुआत में ही हैदराबाद को जोरदार झटका दिया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने ट्रैविस हेड के साथ पारी को संभालना का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई।

### रियान पराग के लिए फैन की दीवानगी, जेल जाने तक को तैयार



गुवाहाटी, 27 मार्च। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के छठे मैच में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। जिसे केकेआर ने 8 विकेट से जीत लिया। वहीं रॉयल्स ने लगातार अपना दूसरा मैच गंवाया है। वहीं गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान एक फैन मैदान तक पहुंच गया और रियान पराग के पैर छूने लगा। बुधवार को रॉयल्स और केकेआर के बीच मुकाबले के दौरान ही कुछ ऐसा ही दुर्घटना को मिला। जहां एक फैन मैदान में घुस गया। ये फैन रियान पराग का था, 12वें ओवर के दौरान ये घटना हुई। सबसे पहले तो फैन ने रियान के पैर छुए और बाद में रियान ने फैन को गले लगाया।

## आईपीएल के बाद ब्रेक लेंगे कप्तान रोहित शर्मा

### इंग्लैंड दौरे पर नहीं होंगे टीम का हिस्सा

नई दिल्ली, 27 मार्च। भारतीय क्रिकेटर्स मौजूदा समय में आईपीएल में जलवा बिखेर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ गए थे। आईपीएल का ये त्यौहार दो महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस दौरे पर रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे। भारत को जून में इंग्लैंड के दौरे पर जाना है। इस दौरे पर वह पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। मैदान तक पहुंच गया और रियान पराग के पैर छूने लगा। बुधवार को रॉयल्स और केकेआर के बीच मुकाबले के दौरान ही कुछ ऐसा ही दुर्घटना को मिला। जहां एक फैन मैदान में घुस गया। ये फैन रियान पराग का था, 12वें ओवर के दौरान ये घटना हुई। सबसे पहले तो फैन ने रियान के पैर छुए और बाद में रियान ने फैन को गले लगाया।



थे। इसके बाद उन्होंने आखिरी मैच से खुद को बाहर करने का फैसला किया था जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने टीम की कप्तानी की थी। रोहित के खुद बाहर हो जाने को संन्यास से जोड़कर देखा जा रहा था। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि उनका खुद को बाहर करने का फैसला संन्यास का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा था कि, ये संन्यास का फैसला नहीं है। मैं इस खेल से दूर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने इस खेल से दूर जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं बल्ले से रन नहीं बना पा रहा था।

# डॉ. प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने वाले सहित छह लोग गिरफ्तार

## तीन लाख रु.का कर्ज और दूसरी जेल में शिफ्ट होने के लिए दी थी धमकी

जयपुर। लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाले सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त गंधीनगर जयपुर पूर्व नारायण बाजिया के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को टीम ने देर रात तक जयपुर जेल में सर्च अभियान चलाया था। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाला शाहनील निवासी शास्त्री नगर जयपुर, वसीम खान निवासी झोटवाड़ा जयपुर,मनीष परिहार निवासी जोधपुर, विक्रमसिंह बडोद जिला साईबाई माधोपुर को सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वॉरंट पर गिरफ्तार किया है और वहीं सिम धाक जुनेद निवासी झोटवाड़ा जयपुर सहित जेल में सिम पहुंचाने वाले अशरफ निवासी झोटवाड़ा जयपुर को भी पकड़ा है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) ने बताया कि पुलिस थाना लाल कोठी जयपुर के इलाके में केंद्रीय कारागार जयपुर से गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम



लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाले सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर के 100 नंबर पर कॉल आया कि उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मरवा देंगे और वह अनिल बोल रहा है। इस पर वारदात को गंभीरता से लेते हुए एक पुलिस टीम गठित की गयी। टीम ने जिस

मोबाइली से फोन किया गया था वह सिम भी जुनेद के नाम से ही थी। जुनेद ने उक्त सिम आरोपी शाहनील तक किस माध्यम से पहुंचाई जिसके संबंध में जांच पड़ताल जारी है। जानकारी में सामने आया कि आरोपित शाहनील ने जेल में ही किराये पर फोन देने का व्यवसाय चला रखा है। वॉर्ड नम्बर 9 में वह बंदियों से प्रत्येक मिनट के 100 रुपये वसूलता है। शाहनील और किन किन बंदियों को मोबाइल बात करने के लिए देता था उस संबंध में पूछताछ जारी है। जिन्होंने उक्त बरामद मोबाइल का उपयोग किया उन कैदियों में से एक बंदी विक्रम सिंह है। जो शाहनील से उक्त मोबाइल लेकर कंट्रोल रूम 100 नंबर पर काल करके उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी दी। विक्रम सिंह के उक्त जेल में तीन लाख रुपये का कर्जा होने के कारण वह दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता था। इसलिए उसने धमकी देना पूछताछ से सामने आया है। आरोपितों के पुछताछ जारी है। इस मामले में जेल प्रशासन व अन्य जिन जिन लोगों की सलिपता है, उस संबंध में अनुसंधान जारी है।

### वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन साल से वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माधुर की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता पुनर्मंचद भंडारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2022 के बाद अब तक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं किए हैं। जबकि हाईकोर्ट के खुद के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर दो साल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया जाना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी नियम बनाकर वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने की गाइड लाइन जारी कर रखी है। इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर स्वयं के नियम नहीं बनाए हैं। जिसके चलते हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ अधिवक्ता अब तक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित नहीं हो पाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया। वकील 1052 दिन से दे रहे धरना- जनवरी, 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता सहित अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता टीएन शर्मा के साथ ही अन्य वकील बीते 1052 दिनों से हाईकोर्ट में धरना दे रहे हैं।

### नए वाहनों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मिलेगी मजबूती : मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस कार्मिक मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम 'सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प' का संकल्प समारोह से 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके लिए पुलिस बल को तमाम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस बल में शामिल हुए इन नए वाहनों से राज्य में आमजन के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने प्रत्येक पुलिसकर्मियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान शर्मा ने पुलिस बेड सहित सभी पुलिस बल के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। पुलिस कार्मिकों का मुख्यमंत्री द्वारा हौसला अफजाई करने पर मनोबल बढ़ा तथा वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, महानिदेशक साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी, महानिदेशक इन्टेलिजेंस संजय अग्रवाल, कुशलक्षेम टी.एन.टी. अनिल पालीवाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस कार्मिक मौजूद रहे।



# अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो रहा सशक्त : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया

- भरतपुर में, आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह में 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
- स्वामित्व योजना में 20 हजार पट्टे एवं माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरित किए गए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को भरतपुर गए, वहां उन्होंने अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित किया। भरतपुर प्रवास के दौरान एम.एस.जे. महाविद्यालय, जहां के वे पूर्व छात्र हैं, में उनका भव्य स्वागत किया।

भरतपुर, 27 मार्च (निस)। गुरुवार को भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों छू रहा है तथा इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। अब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सशक्त होने के साथ ही मुख्यधारा में आ रहा है।

उन्होंने कहा, राजस्थान दिवस उत्सव की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्त्योदय का विचार ब्रज की भूमि से देश-प्रदेश तक पहुंचेगा।

कांग्रेस तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार टूटती करने में व्यस्त थी, जबकि हम जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक घोटाले चरम पर थे, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे गहलोत होटलों में बैठकर सत्ता बचाने की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि का

हस्तांतरण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये (प्रति योजना 100 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की। कार्यक्रम में प्रदेशभर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20 हजार पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चैयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वर्युंअली माध्यम से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गुरु गोलवलकर आशांचित ब्लॉक विकास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट मुफ्त बिजली

योजना की मार्गदर्शिकाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए 'समान अवसर नीति 2025' का विमोचन भी किया। साथ ही, दादरदयाल चुमन्तू सशक्तीकरण योजना, मा नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य

योजना के न्यू पैकेज देने व विधायक जनसुनवाई केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।

## पद्मेश मिश्रा की ए.ए.जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वादनीति एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें किए गए संशोधनों को बड़ी ही बारीकी से देखा जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित कराने के लिए संशोधन नहीं किए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, जो राज्य सरकार की ओर से अदालतों में पेश की जाते हैं। इसलिए इनकी नियुक्ति बहुत ही नीतिगत तरीके से की जानी चाहिए। अपनी अपील में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को नियुक्त करते वक्त उनकी योग्यता, तथा महाधिवक्ता और अन्य महाधिवक्ताओं के बीच कार्यसाधकता के विषय पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया और सीधे ही उनकी नियुक्ति कर दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं।

## मोदी का भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया पुतिन ने

नई दिल्ली, 27 मार्च। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को दी। हालांकि किसी भी पक्ष ने अभी यह नहीं बताया है कि पुतिन का भारत दौरा कब होगा।

लावरोव ने रूसी अंतरराष्ट्रीय मामलों की परिषद की ओर से "रूस और भारत: एक नए द्विपक्षीय एजेंडा की ओर," विषय पर आयोजित सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय

- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत के प्र.मंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना। अब हमारी बारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना था, अब हमारी बारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 06 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोडमैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

## रीट पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को कहा था कि पहले भी कई भर्तियों को एसओजी की जांच के बाद रद्द किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बताता है, लेकिन अन्य राज्यों में रद्द हुई विभिन्न भर्तियों को लेकर संगठन ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। एसओजी मामले में निष्पक्षता से जांच कर रही है। इसलिए जनहित याचिका को खारिज किया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपने ने इनकार करते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

# इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील तीसरे दिन भी हड़ताल पर

वकीलों ने सुप्रीम कोलीजियम के जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले के खिलाफ भारी नारेबाजी

प्रयागराज, 27 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन की हड़ताल में गुरुवार को धरना प्रदर्शन करते हुए जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए गये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट गेट नम्बर तीन पर हुई सभा में पदाधिकारियों संग अधिवक्ताओं ने दोहराया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का हाईकोर्ट में स्थानांतरण मान्य नहीं है। गुरुवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल का लगातार तीसरा दिन है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक न्यायमूर्ति वर्मा के तबादले की

- दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा घर में आग लगने पर कथित तौर नोटों के बंडल मिलने के कारण विवादों में आ गए हैं।

सिफारिश कोलीजियम द्वारा वापस नहीं ली जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने से अदालतों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। प्रतिदिन करीब दस हजार मुकदमों की सुनवाई होती है, लेकिन हड़ताल के कारण तीन

दिन में 30 हजार सुनवाई फंसी हैं। नए मुकदमों की लिस्टिंग पूरी तरह ठप है।

हजारों कैसों में तारीख लग रही है। प्रदेश के तमाम जिलों से आने वाले वादकारी मुकदमों की सुनवाई नहीं होने के कारण परेशान है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ता दल बुधवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिला। बताया जा रहा है बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है। तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल से भी मुलाकात की।

## 'ममता बनर्जी, बांग्लादेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में सर्वाधिक मुखर विरोध किया था और अब सत्ता में आने के बाद, वे वामपंथियों की कार्य योजना का अनुसरण करते हुए विदेशियों को देश में ला रही हैं।

ममता बनर्जी वामपंथी मोर्चे की उदर रणनीति को पूरी तरह उच्चतर स्तर पर ले गई है और उन्होंने इन्हें छिपाने के रास्ते अपनाये हैं। शाह ने कहा कि अधिकांश अवैध चुसपैठियों के पास राज्य सरकार के दफ्तरों द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड राज्य के चौबीस परगना जिले में जारी हुये हैं।

शाह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पकड़े गये इन अवैध चुसपैठियों में से सभी के पास आधार कार्ड थे तथा वे बांगला के गिने-चुने सीमावर्ती जिलों में जारी हुये हैं।

शाह ने कहा कि भारत आर्थिक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में विदेशियों का कुछ मात्रा में प्रवेश तो अपेक्षित है, लेकिन अवैध विदेशियों का प्रवेश बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे जघन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं। बांगला सरकार अपनी संकीर्ण नीतियों के कारण पूरे देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, जो राष्ट्र-हित की दृष्टि से बहुत नुकसानदेह है।

शाह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि गुणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद, ये सारे कृत्य रूक जायेंगे। इस सरकार के संकीर्ण सोच और कृत्यों के चलते, इसके ज्यादा समय तक चलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं।

## 'श्रीलंका की जेलों में 97 भारतीय मछुआरे बंद हैं'

नयी दिल्ली, 27 मार्च। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि अभी 97 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में बंद हैं। डा. जयशंकर ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों में इस संबंध में कड़े कानून बनाये हैं। भारत सरकार मछुआरों की रिहाई के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर समय समय पर बात करती रहती है। उन्होंने कहा कि गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाने वाले मछुआरों की सहायता के लिए सरकार उनकी नौकाओं पर ट्रांसपॉन्डर लगाने का काम कर रही है।

MARUTI SUZUKI

NEXA

अप्रैल में कीमतें बढ़ने से पहले खरीद लें।  
New Age Baleno में अपग्रेड करने के अवसर का लाभ उठाएं।

रीगल एडिशन

₹ 42,760\*

तक की कीमत का एकसेसरी पैकेज पाएं

17<sup>th</sup> March 2025

Maruti Suzuki India Ltd. to hike car prices by up to 4% from April.

Maruti Suzuki India Ltd. announced on March 17<sup>th</sup> that it will increase car prices by up to 4% starting from April 2025, citing rising raw material and operational costs. The price hike will vary across different models.



THE NEW AGE  
**BALENO**  
TECH GOES BOLD



360 व्यू कैमरा



हेड अप डिस्प्ले



6 एयरवेज\*



इन-बिल्ट सुजुकी कनेक्ट

3 years  
100,000 km  
WARRANTY\*  
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

ONLY 04 DAYS LEFT  
₹ 67,100\*\* तक के लाभ

मान्य प्रमाण पत्र जमा करने पर अतिरिक्त स्केपेज बोनस उपलब्ध है।



अपने निकट के शोरूम से जुड़ने के लिए स्कैन करें



E-BOOK TODAY @  
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at  
1800-200-6392  
1800-102-6392

\*\* विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया नज़दीकी डीलरशिप पर जाएं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बिना किसी सूचना के ऑफर्स को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और वेरिफाई के अनुसार ऑफर अलग-अलग हो सकते हैं। ऑफर में सुनिंदा मॉडल/वेरिफाई पर उपभोक्ता ऑफर, एक्सचेंज बोनस और संस्थागत या ग्रामीण ऑफर (जहां भी लागू हो) शामिल हैं। फाइनेंस पर निर्यात क्रेडिट फाइनेंसर द्वारा लिया जाएगा। \*3 साल या 100,000 किमी - जो भी पहले आए। स्केपेज ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए मान्य है और आपको मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और टोयोत्सु इंडिया ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा लाया गया है। \*\* उपरोक्त ऑफर 31 मार्च 2025 तक मान्य है। प्रकाश के प्रभाव से वाहन पर शीशा काला दिखाई देता है। \* रीगल एडिशन किट ₹5000 में गैर-सिग्मा वेरिफाई में उपलब्ध है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा बतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यभट्ट रोड आर्यभट्ट, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908